तिब्बत देश

चीनी जंजाल से मुक्ति के लिए साझा प्रयास जरूरी

पिछले 51 साल से 10 मार्च के दिन को तिब्बत के संदर्भ में खास कारणों से याद किया जाता है। यह दिन चीन के कम्युनिस्ट शासकों के उपनिवेशवादी एजेंडे का नायाब उदाहरण है; तिब्बत में रहने वाली साठ लाख जनता की आजादी की ललक के जिंदा रहने का प्रतीक है; निर्वासन में रहने वाले तिब्बती समाज की लगन और जीवट का भी उदाहरण है और; अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दोगलेपन का भी प्रतीक है।

1959 में इसी दिन तिब्बत की जनता अपने देश पर आठ साल से चले आ रहे चीनी उपनिवेशवादी कब्जे के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। 1951 में चीनी सेना द्वारा तिब्बत के एक बड़े पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने के बाद बीजिंग के नए कम्युनिस्ट शासकों ने दलाई लामा सरकार को चीन में तिब्बत के विलय के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से निहत्थी तिब्बती जनता का मार्च 1959 का यह विरोध कामरेड माओ की चीनी सेना के सामने बहुत देर तक टिक नहीं पाया। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत की राजधानी ल्हासा से उठे इस जन आंदोलन को कुचलने के लिए चीनी सेना ने आरंभिक दौर में ही कम से कम 80 हजार तिब्बतियों की हत्या कर दी थी। इसी दौर में चीनी सेना के हाथों से बचने के लिए तिब्बत के शासक और धर्मनेता दलाई लामा ने भागकर भारत में शरण ली थी।

1959 से परमपावन दलाई लामा भारत में हैं। उनके भारत आने के समय लगभग 80 हजार आम तिब्बती नागरिक निर्वासन में आए थे। लेकिन चीनी अत्याचारों से परेशान तिब्बती नागरिकों का पलायन आज भी जारी है। आज लगभग डेढ़ लाख तिब्बती शरणार्थी भारत और दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। तिब्बती शरणार्थी और दुनिया भर में सक्रिय उनके समर्थक हर साल 10 मार्च का दिन 'तिब्बती जनक्रांति दिवस' के रूप में मनाते हैं। इस दिन चीनी दूतावासों के सामने प्रदर्शन होते हैं, तिब्बत में अब तक चीनी दमन के कारण शहीद हुए 12 लाख से ज्यादा तिब्बतियों के लिए प्रार्थना सभाएं की जाती हैं, तिब्बती जनता के संघर्ष के प्रति समर्थन व्यक्त किया जाता है और दलाई लामा तिब्बती जनता के नाम अपना वार्षिक संदेश जारी करते हैं। जर्मनी में तो पिछले कई साल से सैंकड़ों नगरों के महापौर और नगरपालिकाएं तिब्बती जनता के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए 10 मार्च के दिन अपने सरकारी कार्यालय पर तिब्बत का झंडा भी फहराते हैं। इस साल ऐसे 1100 से अधिक नगरपालिका भवनों पर यह झंडा फहराया गया।

हर साल की तरह इस बार भी परमपावन दलाई लामा का तिब्बती राष्ट्र के नाम संदेश तिब्बत की ताज़ा हालत और वहां चीन सरकार के रवैए पर केंद्रित था। उन्होंने तिब्बती जनता की, खासकर चीन के नियंत्रण में रहने वाले तिब्बतियों की, चीनी दमन के खिलाफ साहस के साथ खड़े रहने और तिब्बत के मुद्दे को जीवित रखने के लिए प्रशंसा की। तिब्बत में शांति स्थापित करने के चीनी दावों के बारे में उनका कहना है कि सेना के बूते पर शांति स्थापित करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि तिब्बत के सवाल का हल निकालने के लिए चीन सरकार के सामने रखी गई उनकी मध्यमार्गी नीति के प्रति भले ही चीन सरकार ने उत्साह नहीं दिखाया लेकिन दुनिया भर में इसे भरपूर समर्थन मिला है। दलाई लामा ने दोहराया है कि इतिहास के किसी भी दौर में तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति का एक शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए वह अपनी इस मध्यमार्गी नीति नीति के तहत तिब्बत पर चीनी शासन मानने को तैयार हैं, बशर्ते चीन सरकार भी तिब्बत की जनता को 'वास्तविक स्वायत्ता' देने के लिए राजी हो जाए। लेकिन चीन सरकार उनके इस प्रस्ताव को यह कह कर बार–बार ठुकराती आ रही है कि इसमें उसे 'चीन को तोड़ने' की बू आती है। 2008 नवंबर में चीन सरकार ने इसी आधार पर धर्मशाला के साथ छह साल से चली आ रही अपनी बातचीत भी तोड़ दी थी।

चीन सरकार के इस अड़ियल रुरव को देखते हुए दलाई लामा ने अपनी रणनीति में एक नया आयाम जोड़ा है। उन्होंने अब चीन के कम्युनिस्ट शासकों के बजाए चीनी जनता के साथ सीधा संवाद करने की नीति अपनायी है। अपने इस बार के वार्षिक संदेश में उन्होंने कहा है कि उनका विरोध चीन सरकार की घोर वामपंथी नीतियों से है, चीनी जनता से नहीं। इसलिए उन्होंने चीनी बुद्धिजीवियों के साथ सीधा संपर्क बनाने की नीति पर चलते हुए विदशों में रहने वाले चीनी विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और लोकतंत्र समर्थकों से मिलकर सीधा संवाद शुरू किया है। उनकी यह नीति अब अपना रंग दिखाने लगी है। अपने संदेश में उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि 2008 के तिब्बती प्रदर्शनों के बाद चीनी पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में तिब्बती बुद्धिजीवियों के 800 से अधिक ऐसे लेख प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें तिब्बती जनता के प्रति सहानुभूति और समर्थन के अलावा चीन सरकार की आलोचना की गई है। पिछले कुछ साल से विदेशों में रहने वाले कई चीनी राजनीतिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी धर्मशाला की यात्रा पर जाने लगे हैं और तिब्बती शरणार्थी संगठनों के साथ उन्होंने संवाद की एक नई प्रक्रिया शुरू की है।

अपने 10 मार्च के संदेश में दलाई लामा ने निर्वासन में रहने वाले तिब्बती समाज की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि उनका समाज न केवल अपनी तिब्बती पहचान और संस्कृति को फिर से स्थापित करने में सफल रहा है बल्कि उसने शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्रों में भी अच्छी उपलब्धियों हासिल की हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष संतोष जताया है कि लगभग दस हजार तिब्बती भिक्षु और भिक्षुणियों ने निर्वासन में तिब्बती बौद्ध धर्म की चारों धाराओं और बॉन धर्म के ऊंचे स्तर के संस्थान खड़े कर लिए हैं। निर्वासन में रह कर तिब्बती समाज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके मुकाबले तिब्बत में चीनी नियंत्रण में चलने वाले मठों के बारे में उनका कहना है कि वहां जबरन कम्युनिस्ट 'पुनर्शिक्षा' के कारण इन मठों की हालत जेलों जैसी है और वे किसी मृत म्यूजियम जैसे दिखते हैं।

अपने इस वार्षिक संदेश में पहली बार दलाई लामा ने चीनी शासन में काम करने वाले तिब्बती अधिकारियों को भी संबोधित किया है। उन्हें तिब्बत में तिब्बती जनता के कल्याण पर ध्यान देने की सलाह देते हुए उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि वे शरणार्थी तिब्बतियों की उपलब्धियां देखने के लिए सरकारी या निजी तौर पर उन स्थानों की यात्रा करें जहां निर्वासित तिब्बती रहते हैं। दलाई लामा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि तिब्बत की समस्या के हल होने के बाद उनके अधिकारों और पदों को सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने तिब्बत के बारे में चीन सरकार के 'पांचवें वर्क फोरम' की भी चर्चा की है जिसने तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र 'टार' के बाहर चीनी प्रांतों के सभी तिब्बती क्षेत्रों में नए विकास कार्य चलाने की सलाह दी है। फोरम की इस सलाह का उदाहरण देते हुए दलाई लामा ने अपनी इस पुरानी मांग को दोहराया है कि सभी तिब्बती बहुल क्षेत्रों के लिए 'वास्तविक स्वायत्ता' पर आधारित साझी प्रशासन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

लेकिन दलाई लामा के इस वक्तव्य का एक खास पहलू सिंकियांग पर उनकी टिप्पणी है जिसे उन्होंने खास तौर से 'पूर्वी तुर्किस्तान' के नाम से संबोधित किया है। वहां चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे दमन और उससे पैदा हुए कठिन हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने वहां की जनता के साथ एकजुटता दिखाई है। उनकी इस टिप्पणी से भले ही चीन सरकार तिलमिलाएगी लेकिन दलाई लामा का यह बयान यह संकेत देता है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार के आतंक और उपनिवेशवाद से पीड़ित सभी समाजों को एक साझा संघर्ष चलाने का समय आ गया है।

– विजय क्रान्ति

लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए परम पावन को अमेरिका का उच्च सम्मान मिला

(वाषिंगटन, 19 फरवरी, 2010)

परम पावन दलाई लामा को अमेरिका का प्रतिष्ठित डेमोक्रेसी सर्विस मेडल दिया गया है। परम पावन दलाई लामा ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान शुक्रवार सुबह वाषिंगटन डीसी में अपने अंतिम कार्यक्रम के तहत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का दौरा किया। लाइब्रेरी में परम पावन का स्वागत वहां के लाइब्रेरियन डॉ जेम्स बिलिंगटन, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी (एनईडी) के अध्यक्ष कार्ल गर्शमन और एनईडी बोर्ड के उपाध्यक्ष जूडी शेल्टन ने की। इसके बाद परम पावन ने लाइब्रेरी में प्रदर्शित व्यापक तिब्बती संग्रह को भी देखा जिसमें गाडेन लाग्यालमा के चित्र वाला एक थांगका भी है। यह थांगपा 13वें दलाई लामा द्वारा अमेरिकी राजदूत एवं विद्वान विलियम रॉकहिल को 21 जून, 1908 को चीन के वुताइस्तान में भेंट किया गया था।

"करीब साल 1952 में मैंने तिब्बत में एक सुधार समिति का गठन कर सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इस समिति ने कुछ कदम उठाए। इसके बाद चीनी प्रशासन को यह रास नहीं आया क्योंकि वे अपनी अलग सुधार प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहे थे। परम पावन ने कहा कि साल 1959 के बाद वे निर्वासन में बने राजनीतिक व्यवस्था में सुधार प्रक्रिया को शुरू करने में सक्षम हुए।

परम पावन दलाई लामा एक संक्षिप्त स्वागत समारोह के बाद ऑडिटोरियम की ओर रवाना हुए। एनईडी के अध्यक्ष कार्ल गर्शमैन ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को इस बारे में बताया कि आखिर क्यों उनके संगठन ने परम पावन दलाई लामा को डेमाक्रेसी सर्विस मेडल के लिए चुना। उन्होंने कहा, "आज हम यहां सिद्धांतों, मूल्यों और लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए दलाई लामा के योगदान को सम्मानित करने के लिए जुटे हुए हैं। उनके इस योगदान को न तो अभी अच्छी तरह समझा गया है और न ही पूरी तरह स्वीकार किया गया है। अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए तिब्बती लोगों के आंदोलन के नेतृत्व के बारे में पूरी दुनिया जानती है और उन्हें एक धार्मिक नेता एवं शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है। लेकिन लोकतंत्र के प्रति उनके इस योगदान को उतना महत्व नहीं मिल पाया है जितने के वह हकदार हैं। आज हमारा उद्देश्य यही है कि उनकी मान्यताओं एवं उद्देश्यों के इस पहलू पर प्रकाश डाला जाए जो दलाई लामा को भविष्य की उस दुनिया के लिए खासतौर से प्रासंगिक बनाते हैं, जिसमें हम रहते हैं।" एनईडी अध्यक्ष ने कहा, "संस्थाओं, मूल्यों और लोकतांत्रिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और हमें एक ऐसा मॉडल पेश करने के लिए कि किस प्रकार लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति बनाई जाए और तिब्बती लोगों एवं तिब्बत की संस्कृति की रक्षा इस तरीके से करने के लिए कि इससे विश्व शांति एवं मानवीय समझ भी बढ़े, परम पावन दलाई लामा को डेमाक्रेसी सर्विस मेडल प्रदान करने में नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी गर्व का अनुभव करती है।"

इसके बाद कार्ल गर्शमैन एवं जूडी शेल्टन ने संयुक्त रूप से परम पावन दलाई लामा को मेडल प्रदान किया और उन्हें सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। मेडल स्वीकार करने के बाद अपने भाषण में परम पावन ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के अपने छोटे से योगदान को स्वीकृति माना। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को किसी औपचारिक शिक्षा से नहीं बल्कि अनुभव से सीखा है। इसके बाद परम पावन ने कुछ उदाहरण दिए कि आखिर कैसे वह इन मूल्यों को सीख पाए। उन्होंने कहा कि साल 1942 में जब वह करीब सात साल के थे तो उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से एक पत्र और उपहार प्राप्त हुआ। लेकिन वह किसी भी बच्चे की तरह उपहार को लेकर ज्यादा उत्सुक थे और पत्र की उन्होंने उपेक्षा कर दी जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि उन्हें तो यह भी भूल गया कि पत्र कहां रखा गया था। उन्होंने बताया कि 68 साल बाद इस गुरुवार को ही उन्हें राष्ट्रपति बराक ओबामा से 1942 के उस पत्र की प्रति हासिल हुई है।

इसके अलावा परम पावन ने बताया कि कई औपचारिक आयोजनों में उन्हें दिन भर राजसिंहासन पर बैठे रहना पड़ता था ताकि आम लोगों से ठीक से बातचीत कर सकें। उन्हें तिब्बत के अपने महल के सफाई कर्मियों से हुंई बातचीत याद है जिससे उन्हें पता चला था कि लोगों को कितनी शिकायतें हैं और समाज में कितना अन्याय है। उन्होंने कहा कि वैसे तो इतिहास में तिब्बत की स्थिति इतनी बुरी नहीं रही है जैसा कि चीनी दुनिया को बताते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां और अन्याय जरूर थे।

परम पावन ने एक और अनुभव को याद करते हुए बताया कि उन्हें 1954 में चीन और 1956 में भारत का दौरा करना पड़ा था जिसके दौरान वह दोनों देशों की संसदीय कार्यवाही को देख पाए। परम पावन ने कहा कि चीन की संसद में एक सत्र के दौरान ऐसा लगा कि एक सदस्य कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी कर रहा है। इसके बाद उन्हें याद है कि तत्काल एक अधिकारी ने उन्हें अपनी जबान पर लगाम रखने को कहा। दूसरी तरफ, भारतीय संसद में उन्होंने देखा कि कार्यवाही काफी जीवंत और शोर–शराबे वाली है,

बल्कि वहां लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। परम पावन ने कहा कि जब वह चीनी प्रधानमंत्री झू एन लाई से मिले तो उन्होंने उनको इस अनुभव के बारे में बताया। परम पावन ने कहा कि दोनों देशों के बीच इस अंतर से एक एकाधिकारवादी समाज और एक खुले समाज का अंतर पता चलता है। परम पावन ने एक और अनुभव को याद किया जब 1959 में उनकी भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से मुलाकात हुई थी। परम पावन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि तिब्बत मसले को संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी इसके खिलाफ थे। इसके बावजूद तिब्बतियों ने इस मसले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। परम पावन ने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू के साथ हुई मुलाकात में वह थोड़ा घबराए हुए थे कि प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया न जाने क्या होगी क्योंकि हमने उनकी सलाह नहीं मानी थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने नाराजगी का कोई भी लक्षण नहीं दिखाया। तब मुझे लोकतंत्र की इस ताकत का पता चला कि लोग बिना किसी डर के एक–दूसरे से के विचार के खिलाफ हो सकते हैं। परम पावन ने कहा कि ऐसे अनुभवों से ही उन्हें कई बार लोकतंत्र के बारे में जानने और उसके गुणों की सराहना करने का मौका मिला।

परम पावन ने कहा, "करीब साल 1952 में मैंने तिब्बत में एक सुधार समिति का गठन कर सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इस समिति ने कुछ कदम उठाए। इसके बाद चीनी प्रशासन को यह रास नहीं आया क्योंकि वे अपनी अलग सुधार प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहे थे। परम पावन ने कहा कि साल 1959 के बाद वे निर्वासन में बने राजनीतिक व्यवस्था में सुधार प्रक्रिया को शुरू करने में सक्षम हुए। परम पावन ने कहा कि 1969 में उन्होंने औपचारिक तौर पर यह साफ कर दिया कि दलाई लामा की संस्था का भविष्य तिब्बती जनता के हाथ में ही है, वे ही यह तय करेंगे कि इस संस्था से उन्हें कोई लाभ है या नहीं। अपनी भूमिका का उल्लेख करते हुए परम पावन ने कहा, "मैंने अक्सर यह कहा है कि 14वें दलाई लामा निश्चित रूप से सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन वह सबसे खराब भी नहीं हैं। लोकतांत्रिक बदलाव तब आया जब साल 2001 में राजनीतिक सत्ता चुने हुए नेतृत्व के हाथ में सौंपी गई। इस सभा के श्रोताओं में एक मानवाधिकार रक्षक सम्मेलन के प्रतिनिधि भी शामिल थे, इसलिए परम पावन ने इस अवसर का उपयोग उनके कार्यों की भूरि–भूरि प्रशंसा के लिए भी की। परम पावन ने कहा कि वह मानवाधिकार को सिर्फ एक व्यक्ति की चिंता नहीं, बल्कि पूरे समाज की चिंता मानते हैं। परम पावन ने कहा, "किसी व्यक्ति के अधिकारों को बचाने का मतलब है कि समाज में विकास और प्रगति को बचाना। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है।" उन्होंने स्मरण किया कि जब तिब्बतियों को शरणार्थी बन जाना पड़ा तो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने सबसे अपने हाथ में सबसे पहला लक्ष्य स्कूलों की स्थापना का लिया।

परम पावन ने कहा कि तिब्बत में रहने वाले तिब्बती हमारे "असली मालिक" हैं और उन्होंने तिब्बती बौद्ध संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। परम पावन ने बौद्ध विज्ञान, बौद्ध अवधारणा और बौद्ध धर्म के तीन बौद्ध श्रेणियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहली दो श्रेणी हर किसी के लिए प्रासंगिक है, लेकिन बौद्ध धर्म का संबंध सिर्फ बौद्धों से है।

अपने संबोधन के बाद परम पावन ने श्रोताओं द्वारा पूछे जाने वाले कुछ सवालों के भी जवाब दिए। एक सवाल यह था कि लोकतांत्रिक भारत और कम्युनिस्ट चीन में से भविष्य में ज्यादा प्रासंगिक कौन होगा। इस सवाल के जवाब में परम पावन ने भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक "संत प्रधानमंत्री" बताया, उन्होंने भारतीय समाज की प्रकृति के बारे में बताते हुए यह साबित किया कि आखिर क्यों भारतीय व्यवस्था ज्यादा प्रासंगिक है। एक और सवाल के जवाब में परम पावन ने कहा कि चीनी नेताओं को उनके इस बयान की सराहना करनी चाहिए कि कम्युनिस्ट व्यवस्था को "सम्मान के साथ" विदा कर दिया जाए। परम पावन ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रह सकता। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कई गलत काम किए हैं, लेकिन इसके साथ ही उसने चीन को मजबूत बनाने में काफी कुछ योगदान किया है। इसलिए उनका मानना है कि इस पार्टी को सम्मान के साथ सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए।

परम पावन ने अंत में अपनी इस मान्यता को सब तक पहुंचाया कि सभी मनुष्य एक हैं और करुणा के आधार पर हम सबके अंदर आंतरिक ताकत के विकास करने की समान क्षमता है। उनके इस भाषण के बाद जूली शेल्टन ने परम पावन का धन्यवाद दिया और उनकी पुस्तक दि आर्ट ऑफ हैपिनेस को उद्धृत करते हुए कहा कि आपने हमें काफी खुशी दी है।

कोई भी राजनीतिक दल हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रह सकता। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कई गलत काम किए हैं, लेकिन इसके साथ ही उसने चीन को मजबूत बनाने में काफी कुछ योगदान किया है। इसलिए उनका मानना है कि इस पार्टी को सम्मान के साथ सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने परम पावन दलाई लामा को मजबूत समर्थन दिया

(वाशिंगटन डीसी, 18 फरवरी, 2010)

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गुरुवार सुबह को परम पावन 14वें दलाई लामा से मिले। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने तिब्बत की विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान और चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपना मजबूत समर्थन जताया। इस दौरान राष्ट्रपति ने दलाई लामा के मध्यम मार्ग नीति, अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और चीन सरकार के साथ बातचीत करते रहने के उनके प्रयास की सराहना की।

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने दोनों पक्षों को लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे अपने मतभेदों को दूर करने के लिए सीधे संवाद करें और हाल में वार्ता की फिर से शुरुआत होने की बात सुनकर उन्हें खुशी हुई है। परम पावन और दलाई लामा इस बात पर सहमत थे कि अमेरिका एवं चीन के बीच एक सकारात्मक एवं सहकारी संबंध होने चाहिए।

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने दोनों पक्षों को लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे अपने मतभेदों को दूर करने के लिए सीधे संवाद करें और हाल में वार्ता की फिर से शुरुआत होने की बात सुनकर उन्हें खुशी हुई है। परम पावन और दलाई लामा इस बात पर सहमत थे कि अमेरिका एवं चीन के बीच एक सकारात्मक एवं सहकारी संबंध होने चाहिए।

परम पावन दलाई लामा के विशेष दूत लोदी ग्यारी ने इस मुलाकात के बारे में कहा, "आज की मुलाकात से यह बात साफ हुई है कि राष्ट्रपति ओबामा तिब्बत के मसले को हल करने के लिए परम पावन दलाई लामा के प्रयासों का समर्थन करते हैं और व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं।"

बिहार के मुख्यमंत्री परम पावन दलाई लामा से मिले

(धर्मशाला, 8 फरवरी)

भारत के बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धर्मशाला में सोमवार को परम पावन दलाई लामा से उनके निवास पर मुलाकात की। कालोन ट्रिपा प्रोफेसर सामदांग रिनपोछे के नेतृत्व में कशग ने मुख्यमंत्री के सम्मान में रविवार को रात्रिभोज दिया था। कशग के सचिव मिंगयूर दोरजी ने टिबेटनेट को यह जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परम पावन दलाई लामा को पटना जाने और तेजस्वी बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन करने का औपचारिक निमंत्रण देने पहुंचे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह पार्क अप्रैल–मई तक तैयार हो जाएगा। पटना रेलवे स्टेशन के पास बन रहे इस विशाल पार्क के निर्माण पर करीब 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें ध्यान के लिए एक हॉल भी होगा। यह पार्क भगवान के बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2550वें वर्ष के अवसर पर बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार संभवतः परम पावन से इस बात के लिए समर्थन भी मांगेंगे कि पार्क में भगवान बुद्ध के पवित्र चिह्नों वाले कलश को रखा जाए ताकि आम जनता इनके दर्शन कर सके। फिलहाल भगवान बुद्ध के यह पवित्र चिह्न करीब 60 साल से पटना संग्रहालय में रखे गए हैं। इन्हें वैशाली में खुदाई के दौरान हासिल किया गया था। इस बात की उम्मीद है कि परम पावन और नीतीश कुमार की मुलाकात के दौरान ही इस पार्क के उद्घाटन की तिथि को अंतिम रूप दिया जाएगा।

परम पावन पटना में 27 मई को बुद्ध पार्क का उद्घाटन करेंगे

(धर्मशाला, 9 फरवरी)

बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आगामी 27 मई को परम पावन दलाई लामा पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन करेंगे। सोमवार को परम पावन के निवास पर उनके और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई एक घंटे की मुलाकात के दौरान उन्होंने इस पार्क के उद्घाटन का मुख्यमंत्री का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक ध्यान केंद्र सहित यह पार्क पटना जंक्शन से सटे हुए शहर के बीचोंबीच 22 एकड़ जमीन पर बन रहा है। इसके बीच में भगवान बुद्ध की एक विशालकाय मूर्ति होगी। इस पार्क की लागत पर करीब 125 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से बातचीत में नीतीश कुमार ने बताया, "परम पावन ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा की है और उन्होंने यह भी वायदा किया है कि बुद्ध से जुड़े पवित्र चिह्नों को दान किया जाएगा ताकि उन्हें पार्क का अतिरिक्त आकर्षण बनाया जा सके।"

भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2550 साल पूरा होने के अवसर पर राज्य सरकार बौद्ध निर्माण मॉडल के आधार पर ही इस पार्क का निर्माण करा रही है। परम पावन दलाई लामा पार्क में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति का अनावरण करेंगे। नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने परम पावन दलाई लामा को प्रस्तावित नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी दी है जिस पर काम चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री रविवार को धर्मशाला पहुंचे थे और उसी दिन रात में कशग ने उनके

सम्मान में एक भोज दिया था।

चीनी अदालत ने एक तिब्बती नागरिक को मौत की सजा दी

(धर्मशाला, शुक्रवार, 26 फरवरी, 2010)

तिब्बत की एक चीनी अदालत ने एक तिब्बती नागरिक को दो साल के लिए विलंबित मौत की सजा और एक अन्य नागरिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों नागरिकों पर आरोप था कि उन्होंने अलगाववाद को बढ़ावा दिया है और सामाजिक व्यवस्था को भंग किया है। धर्मशाला की एक मानवाधिकार संस्था ने यह जानकारी दी है। कार्जे माध्यमिक जन न्यायालय ने 28 साल के पेमा येशी को 17 नवंबर, 2009 को दो साल के लिए विलंबित मौत की सजा सुनाई है। इसी प्रकार 24 साल के सोनम गोनपो को आजवीन कारावास और 32 साल के सेवांग ग्यात्सो उर्फ सोक सोक को 16 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। ये सभी नागरिक न्यारांग काउंटी के थांगकी टाउनशिप के निवासी हैं। तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) ने कुछ भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इनके गिरफ्तारी की खबर एक स्थानीय अखबार गांजी डेली में 18 मार्च, 2009 को छपी थी। इस खबर के अनुसार, "तीन तिब्बती आरोपियों को 11 मार्च, 2009 को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने थांगक्यी टाउनशिप, न्यारांग काउंटी की सड़कों पर तिब्बत की आजादी के आह्वान वाले पोस्टर चिपकाए और लोगों को बांटे और 28 फरवरी को थांगक्यी टाउनशिप की सरकारी इमारत को आग लगा दी जिससे सरकारी खजाने को करीब 2 लाख यूआन का नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार उनकी गिरफ्तारी के पांच माह तक किसी को भी यह पता नहीं रहा कि उन्हें कहां और किस दशा में रखा गया है। इनकी गिरफ्तारी के पांच माह बाद जाकर ही अगस्त में परिवार के सदस्यों को यह पता चल पाया उन्हें चेंगदू जन सुरक्षा ब्यूरो में कैद रखा गया है।

स्थानीय अधिकारियों ने 10 दिसंबर, 2009 को इन लोगों के परिवार के सदस्यों को अदालत के आदेश के बारे में बताया। टीसीएचआरडी ने कहा इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि इन आरोपियों को चीनी कानून के तहत मिलने वाले बुनियादी कानूनी अधिकारों से भी वंचित रखा गया होगा क्योंकि उन पर मुकदमा पूरी तरह गोपनीय तरीके से चलाया गया और उसमें उनकी पसंद का वकील भी नहीं रखा गया। सोनम गोनपो और सेवांग ग्यात्सो, दोनों न्यारांग काउंटी के थांगकी टाउनशिप के थांगकी प्राइमरी स्कूल में कुक का काम करते थे। उन्हें फिलहाल कार्जे के देयांग सिटी के पीएसबी कारावास केंद्र में रखा गया है। दूसरी तरफ, थांगकी टाउनशिप के किसान पेमा येशी को खम प्रांत के दार्तसेडो पीएसबी कारावास केंद्र में रखा गया है। पेमा येशी को दो साल के लिए विलंबित मौत की सजा दी गई है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये तीनों नागरिक पिछले साल तिब्बत में मारे गए लोगों को श्रंद्धाजलि देने और अभी तक जेल में बंद तिब्बती नागरिकों के प्रति समर्थन जताने के लिए तिब्बतियो द्वारा चलाए जा रहे खेती बहिष्कार आंदोलन और लोसार न मनाने के आंदोलन में सक्रियता से शामिल हुए थे।

चीन के बुद्धिजीवियों से मिल रहे समर्थन से दलाई लामा उत्साहित

(धर्मशाला, 22 फरवरी)

परम पावन दलाई लामा शुक्रवार को लॉस एजिलिस पहुंचे जहां वह व्होल चाइल्ड इंटरनेशल (डब्ल्यूसीआई) के समर्थन में एक सप्ताह तक रुकेंगे। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो अनाथ एवं वंचित बच्चों के लिए काम करता है। लॉस एजिलिस टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में परम पावन ने कहा, "तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता देने के उनके आह्वान पर होने वाली चीन से नवीनतम वार्ता में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।" इसके बावजूद परम पावन ने कहा कि चीनी लोगों की तरफ से बढ़ते समर्थन की वजह से इस मामले में प्रगति हो सकती है। परम पावन ने लॉस एजिलिस टाइम्स से कहा, "बहुत से चीनी बुद्धिजीवी और लेखक सामने आ रहे हैं और वे हमारे मध्यम मार्ग नीति का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वे चीन सरकार की नीतियों की भी जमकर आलोचना कर रहे हैं। परम पावन ने कहा, चीनी बुद्धिजीवियों में साल 2008 में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बाद तिब्बत के प्रति सहानुभूति और बढ़ गई है। इन प्रदर्शनों पर चीनी अधिकारियों ने तेजी से और हिंसक प्रतिक्रिया की थी। परम पावन ने कहा कि इसके बाद वे कई ऐसे चीनी नागरिकों से मिले हैं जिनका कहना है कि इन प्रदर्शनों के पहले वे तिब्बत की समस्या से अनजान थे। अब उनको लगता है कि चीन के एक हिस्से के रूप में ही स्वशासी तिब्बत की हमारी मांग काफी उचित और तार्किक है। परम पावन ने कहा, चीनी लेखकों ने तिब्बत

"बहुत से चीनी बुद्धिजीवी और लेखक सामने आ रहे हैं और वे हमारे मध्यम मार्ग नीति का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वे चीन सरकार की नीतियों की भी जमकर आलोचना कर रहे हैं। परम पावन ने कहा, चीनी बुद्धिजीवियों में साल 2008 में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बाद तिब्बत के प्रति सहानुभूति और बढ़ गई है।

में स्वायत्तता के समर्थन में करीब 800 लेखक लिखे हैं जिसमें से करीब 300 चीन में ही प्रकाशित हुए हैं। परम पावन ने गुरुवार को राष्ट्रपति ओबामा से अपनी मुलाकात की संक्षिप्त चर्चा भी की। परम पावन ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति से इसलिए मिले क्योंकि, "यह मेरा कर्तव्य था कि चीन सरकार के साथ अपने संबंधों की स्थिति की उन्हें जानकारी या रिपोर्ट दें।" इस बारे में सवाल पर कि क्या चीन से रिश्तों के मामले में कोई प्रगति हुई है, परम पावन ने कहा, "कोई प्रगति नहीं हो पाई है, हमेशा चीनी अधिकारियों का रवैया सख्त रहा है। न केवल तिब्बतियों के खिलाफ बल्कि अपनी जनता के भी खिलाफ।" परम पावन अपनी इस यात्रा के दौरान शनिवार को एक भोज के अवसर पर भाषण देंगे और रविवार को गिब्सन एंफीथिएटर में वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे, यहां उनके साथ संगीतकार शेरिल क्रो भी होंगे।

तिब्बती जनक्रांति दिवस की 51वीं वर्षगांठ पर पावन दलाई लामा का वक्तव्य

आज चीनी दमन के विरूद्ध 1959 में तिब्बती के लोगों द्वारा शान्तिमय विद्रोह की 51वीं वर्षगांठ है तथा मार्च 2008 में समूचे तिब्बत में फूटे विरोध की दूसरे वर्षगांठ। इस अवसर पर मैं तिब्बत के उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने तिब्बत के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया तथा जो लोग अब तक तिब्बत में यातनाएं झेल रहे हैं उनके दुःखों के शीघ्र अन्त के लिए प्रार्थना करता हूँ। कई दषकों से अनेक मुषिकलों का सामना करने के बावजूद तिब्बती लोग अपना सानहस तथा संकल्प संजोए रखने, अपनी करूणामयी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी अस्मिता को कायम रखने में सफल रहे हैं। यह बात भी प्रेरणादायक है कि तिब्बतियों की एक नई पीढ़ी तिब्बत के सरकारों को सजीव रख रही हैं। मैं उन तिब्बती लोगों के जो अब भी भय और दमन को सहन कर रहे हैं उनके साहस को प्रणाम करता हूँ। हम चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में हों सभी तिब्बतियों का यह दायित्व है कि वे अपनी विषिष्ट पहचान तथा संस्कृति की रक्षा करते हुए भी अन्य राष्ट्रीय इकाईयों के बीच समता, समरसता तथा एकता बनाए रखें । तिब्बत के अनेक भागों में बहुत से तिब्बती पार्टी, सरकार तथा सेना में जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे हैं तथा तिब्बतियों की यदासम्भव सहायता कर रहे हैं। अब तक उनके द्वारा दिए गए सकारात्मक योगदान की हम सराहना करते हैं। जाहिर है कि जब निकट भविष्य में तिब्बत सार्थक स्वायत्तता प्राप्त कर लेंगे तो उन लोगों को वैसे ही उत्तरदायित्व निभाते रहना होगा। मैं यह दुहारना चाहूंगा कि एक बार जब तिब्बत की समस्या का समाधान हो गया तो मैं कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करुंगा और न ही निर्वासित सरकार के सदस्य तिब्बती प्रषासन में कोई पद ग्रहण करेंगे। भूत में भी में निरंतर इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं निमंत्रण देता हूँ उन तिब्बती अधिकारियों को जो तिब्बत के कई स्वायत प्रभागों में कार्यरत है कि निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की दषा और दिषा को समझने हेतु वे आऐं और स्वतंत्र देषों में रह रहे तिब्बती समाजों से चाहे सरकारी या गैर तौर पर मिलें तथा स्वयं हालात का जायता लें। निर्वासित तिब्बती जहां भी जा कर बसे हैं वही उन्होंने तिब्बत के प्रष्न पर जागरुकता पैदा करने के अतिरिक्त अपनी विषिष्ट सांस्कृतिक तथा आद्यात्मिक परम्पराओं का संरक्षण और सवर्धन भी किया है। अन्य शरणार्थियों के विपरीत हम अपेक्षतः अधिक सफल रहे हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने पारम्परिक मूल्यों के अनुरुप उनका पालन पोषण करते हूए भी ठोस आधुनिक षिक्षा उपलब्ध करवा पाए हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म की चार प्रमुख शाखाओं तथा बौन धर्म के अध्यक्ष भी निर्वासन मे हैं धार्मिक प्रषिक्षण तथा चयर्या हेतु अनेक संस्थाओं को भी स्थापित कर सके हैं। इन संस्थाओं में 10,000 भिक्षु और भिक्षुणिाओं को अपना काम काज करने की स्वतंत्रता है। तिब्बत से निरंतर चले आ रहे भिक्षु तथा भिक्षुणिओं और छात्रों के लिए भी षिक्षा के अवसर प्रदान करने में हम सफल रहे हैं। साथ ही पूर्व और पषिचम के देषों में बौद्ध धर्म के अमूत पूर्व प्रसार तथा भविष्य में उसके समृद्ध होने की संभावना से हम आषन्वित हुए है कि वन सुरक्षित रहेगा। तिब्बत के इतिहास के सर्वाधिक संकटमय इस दौर में यह हमारे लिए बड़ी सांत्वना की बात है।

वर्तमान में चीनी अधिकारी तिब्बत के मठों में कई राजनीतिक अभियान चला रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पुनर षिक्षण । भिक्षु तथा भिक्षुणिओं को उन्होंने बन्दीगृह जैसी स्थिति में डाल रखा है और शान्ति से अपनी चयर्याऐं करने तथा षिक्षा पाने से वंचित कर रखा है। इन परिस्थितियों में मठ केवल अजायब घर बन कर रह गए हैं। बौद्ध धर्म के करूणा और अहिंसा के सिद्धान्तो पर आधारित तिब्बती संस्कृति न केवल तिब्बती लोगों बल्कि चीनीयों समेत समस्त विष्व के लोगों के लिए हितकर है। अतः हम तिब्बतियों को केवल भौतिक प्रगति पर ही ध्यान न देकर बल्कि तिब्बत के भीतर और तिब्बत से बाहरी रह हरे तिब्बतियों को अपने पारम्परिक मूल्यों के साथ साथ आधुनिक षिक्षा को भी उदार बनाना चाहिए। अधिक युवा तिब्बतियों को विषेषज्ञों तथा दक्ष व्यवसायिक बनना चाहिए। आवषयक है कि तिब्बती लोग न केवल अन्य

तिब्बत के अनेक भागों में बहुत से तिब्बती पार्टी, सरकार तथा सेना में जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे हैं तथा तिब्बतियों की यदासम्भव सहायता कर रहे हैं। अब तक उनके द्वारा दिए गए सकारात्मक योगदान की हम सराहना करते हैं।

राष्ट्रीय लोगों के साथ मैत्री रखें बल्कि अपने लोगों से भी और आपस के छोटे छोटे झगड़ों में न पड़े। मैं उन से अनुरोध करूगा कि आपस के मतभेद शान्ति तथा धैर्य से सुलझाऐं। चीनी प्रषासन स्वीकार करे या न करे परन्तु तिब्बत के सम्बन्ध में गम्भीर समस्या तो हैं ही। सारा संसार जानता हैं कि तिब्बत में बड़े पैमाने पर सेना की उपस्थिति तथा तिब्बत यात्रा पर लगे प्रतिबन्ध इसका स्पष्ट प्रमाण है। यह हम दोनों में से किसी के हित में नही। हमें समस्या के समाधान हेतु अवसर का उपयोग करना होगा। गत तीस वर्ष से अधिक समय से दोनों पक्षों के लिए लाभकरी अपने मध्यमार्गीय सिद्धांत द्वारा मैं ने तिब्बत समस्या के समाधान हेतु चीन के जनवादी लोकतंत्र से बात करने की चेष्टा की है। यद्यामि मैने तिब्बत की आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से उदाहन्त किया है, जो कि चीनी संविधान तथा प्रदेषक स्वायत्तता के प्रावधानों के अनुकूल हैं, तो भी उस का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। वर्तमान चीनी नेतृत्व के रुख को देखते हुए कोई उम्मीद नहीं कि निकट भविष्य में भी कोई परिणाम निकले। हां वार्तालाप के हित में हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नही है।

गर्व और सन्तोष का विषय है कि दोनों पक्षों के लिये पारस्पारिक तौर पर हितकर हमारे मध्यमार्गीय दृष्टिकोण तथा तिब्बती संघर्ष के न्यायोचित होने की बात को वर्ष प्रतिवर्ष अनेक धर्मआगुओं और राजनीतिक नेताओं ने अधिकारिक रूप में समझा और स्वीकारा है, जिन में शामिल है अमरीका के राष्ट्रपति, विख्यत गैर–सरकारी संस्थएं, विष्व समाज तथा विषेषकर, चीनी बुद्धिजीवी। स्पष्ट है कि तिब्बत की समस्या चीनी और तिब्बती जनता के बीच का विवाद नहीं बल्कि इस का कारण है चीनी समाजवादी प्रषासन की अतिवादी वाम दलीय नीतियां। तिब्बत में 2008 के प्रदर्षनों के बाद से चीन के भीतर और बाहरी रहने वाले चीनी बुद्धिजिवियों ने तिब्बत समस्या से सम्बन्धित 800 से भी अधिक निष्पक्ष लेख लिखें है। अपनी विदेष यात्राओं के दौरान में जहां भी जाता हूं तो जब मेरी साधारणतयः चीनियों से भेट होती है, विषेष कर बुद्धिजीवियों और छात्रों से, तो वे अपनी हार्दिक सहानुभूति और सहायत का प्रकटीकरण करते हैं। क्योंकि चीन तिब्बत समस्या का समाधान, अन्ततोगत्वा, दोनों देषों की जनता के बीच होना है, इसलिये जहां भी हो सके मै आपस में सूझबूझ स्थापित करने के उदेष्य से चीनी लोगों के प्रति हाथ बढ़ाता हूँ। अतः तिब्बतियों के लिये हर जगह यह बहुत जरूरी है कि वे चीनियों के साथ निकट सम्बन्ध बनाऐं तथा तिब्बत के सत्य के बारे और तिब्बत के वर्तमान हालात से उन्हें अवगत कराऐं। आईए हम पूर्वी तुर्कस्तान के लोगों का भी स्मरण करे जिन्होंने महान विपत्तियां तथा अधिकाधिक यातनाएं झेली है, उन चीनी बुद्धिजीवियों के भी याद करे जो अधिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष–रत है और जिन्हें कठोर दण्ड मिला है। मै उनके साथ अपनी एकात्मता प्रकट करता हूँ तथा दृढ़ता से उनके साथ हूँ। बहुत आवषयक है कि चीन की 1.3 अरब जनता को अपने तथा अन्यों के बारे में सूचना पाने की स्वतंत्रता हो और साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हो तथा कानून का शासन चले। यदि चीन में अधिक पारदर्षिता हो तो विष्वास में वृद्धि होगी जिसके परिणाम स्वरूप समरसता, स्थिरता तथा प्रगति को बल मिलेगा। अतःहर किसी को इस दिषा में प्रयत्र करना चाहिए। तिब्बती जनता के एक स्वतंत्र प्रवक्ता के नाते मै बार बार उन की आकांक्षओं की व्याख्या चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य के नेताओं के समक्ष कर चुका हूँ। उनकी और से सकारात्मक प्रतिक्रिया का अभाव निराषजनक है। यद्यपि वर्तमान प्रषासन अपने कठोरवादी पक्ष से चिमटा भी रहे तो भी, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रहे बदलावों को देखते हुए तथा चीनी जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन के संदर्भ में, कहा जा सकता है कि समय आएगा जब विजय सत्य की ही होगी। अतः यह जरूरी है कि सभी धैर्य रखें और आस न छोड़े। पांचवें तिब्बत वर्क फोरम के अवसर पर लिये गए केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं कि भविष्य में प्रगति और विकास के लिए सभी तिब्बती प्रदेषों में समान नीति लागू की जाएगी। नेषनल पीपुल्ज़ कान्फैंस के हाल ही में हुए अधिवेषन में प्रधानमंत्री वेन जिया बाओ ने भी इस की पुष्टि की । यह हमारी बार बार दुहराई जाने वाली मांग के अनुरूप है कि सभी तिब्बती प्रदेषों के लिए समान प्रषासनिक व्यवस्था हो। इसी प्रकार तिब्बती इलाकों में हुए विकास की भी हम सरहाना करते हैं, विषेषतः घुमनाओं और कृषि से जुडे क्षेत्रों में। हां, हमें सतर्क रहना चाहिए कि यह विकास हमारी मूल्यवान संस्कृति, भाषा तथा तिब्बत के प्राकृतिक पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो जिस का सम्बन्ध समस्त ऐषिया के कल्याण से जुडा है।

इस अवसर पर मै अपना हार्दिक अभार प्रकट करना चाहूंगा उन अनेक देषों के नेताओं और उनके बुद्धिजीवियों, जन साधारण, तिब्बत समर्थक तथा उन सभी के प्रति जो सत्य और न्याय के पक्षधर है और चीनी सरकार के दबाव तथा उत्पीड़न के बावजूद भी तिब्बत के प्रष्न पर हमारा समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार, प्रदेष सरकारों तथा भारत की जनता के प्रति मैं विषेष रूप से उनके निरन्तर तथा उदार समर्थन के लिये दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।

दलाई लामा
10 मार्च, 2010

तिब्बती जनता के एक स्वतंत्र प्रवक्ता के नाते मै बार बार उन की आकांक्षओं की व्याख्या चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य के नेताओं के समक्ष कर चुका हूँ। उनकी और से सकारात्मक प्रतिक्रिया का अभाव निराषजनक है।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आ

1 *धर्मषाला में परम पावन दलाई लामा के साथ चीनी प्रतिनिधिमंडल, इस प्रतिनिधिमंड*
2. *धर्मषाला में आयोजित आईटीएसएन एषिया क्षेत्रीय बैठक में शामिल टीएसजी सदस्*
3. *धर्मषाला में 26 मार्च, 2010 को इंटरनेषनल टिबेट सपोर्ट नेटवर्क एषिया की तीन दि सामदांग रिनपोछे (बीच में)*
4. *धर्मषाला के टीआईपीए में ष्शोटॉन फेस्टिवल की 27 मार्च को शुरुआत हुई, यह उ*
5. *तिब्बती फिल्म "द सन बिहाइंड द क्लाउड्स" को 12 मार्च, 2010 को 12वें वार्षिक अवार्ड दिया गया*
6. *तिब्बत की राजधानी ल्हासा के पोटाला महल के सामने हो रही खुदाई कार्य से भूमि दुनिया की बेषकीमती विरासत की पहचान को गंभीर चुनौती मिल रही है*
7. *धर्मषाला में 10 मार्च 2010 को 51वें तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस के अवसर पर "टिबेटन रोड टु फ्रीडम" का अनावरण किया*
8. *चीन–तिब्बत वार्ता के लिए गठित टास्क फोर्स की 21वीं बैठक धर्मषाला में 23 से*
9. *तिब्बत के लिए एच पी विधानसभा विधायक मंच के पुनर्गठन के अवसर पर षिमल से मुलाकात के दौरान निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर श्रीमती डोलमा*
10. *परम पावन दलाई लामा मध्य प्रदेष विधानसभा को संबोधित करने के लिए 17 माच*

(9)

(8)

♦ आंखों देखी

(3)

(4)

की आंख से

तिनिधिमंडल ने तिब्बत की सार्थक स्वायत्तता को प्रबल समर्थन दिया
जी सदस्य और प्रेक्षक
की तीन दिवसीय क्षेत्रीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कालोन ट्रिपा,

ई, यह उत्सव 4 अप्रैल तक चलेगा
वें वार्षिक वन वर्ल्ड इंटरनेषनल ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटरी फिल्म फेस्टिवल के दौरान

र्य से भूमिगत स्तर पर बाढ़ आने का खतरा है जिससे तिब्बती जनता के अस्तित्व और

अवसर पर वीमिंग चेन (तस्वीर में नहीं दिख रहे) ने तिब्बती संग्रहालय में एक प्रतिमा

में 23 से 25 मार्च, 2010 तक हुई
पर षिमला में 5 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल (दाएं से पहले)
डोलमा ग्यारी (बाएं से पहले)
ए 17 मार्च, 2010 को भोपाल पहुंचे

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

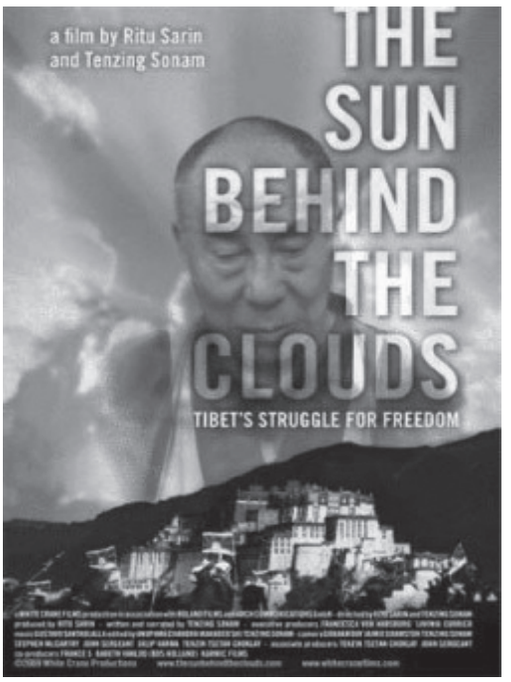

(7)

(6)

तिब्बती जनता को वास्तविक स्वायत्तता के लिए दिए गए ज्ञापन पर नोट

साल 1979 में चीनी नेता दैंग जियोपिंग ने तिब्बत की आज़ादी के अलावा अन्य सभी मसलों पर बातचीत एवं उसे हल करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद से परम पावन दलाई लामा ने तिब्बत के मसले के हल के लिए एक परस्पर स्वीकार्य बातचीत से हल निकालने के लिए कई प्रयास किए। ऐसा करके परम पावन दलाई लामा ने मध्यम मार्ग नीति का अटल रूप से पालन किया जिसका मतलब यह था कि मेलमिलाप और समझौते की भावना के द्वारा एक परस्पर स्वीकार्य और परस्पर लाभ वाला हल निकाला जा सके।

इस नोट में तिब्बती जनता को वास्तविक स्वायत्तता देने के लिए दिए गए ज्ञापन पर चीन सरकार द्वारा उठाए गई मुख्य चिंताओं और आपत्तियों का समाधान किया गया है। यह ज्ञापन 31 अक्टूबर, 2008 को बीजिंग में आठवें दौर की वार्ता में चीन जनवादी गणराज्य की सरकार को दिया गया था। चीन के मंत्री ड्यू क्विंगलिन और कार्यकारी उप मंत्री झू द्वारा वार्ता के दौरान दी गई प्रतिक्रिया, लिखित टिप्पणी और वार्ता के बाद चीन सरकार द्वारा जारी बयान के गंभीरता से अध्ययन के बाद हमें ऐसा लगा कि ज्ञापन में उठाए गए कुछ मसलों को गलत तरीके से समझा गया है, जबकि कुछ और मसलों को चीन सरकार समझ नहीं पाई है।

चीन की केंद्रीय सरकार लगातार कहती रही है कि यह ज्ञापन चीन जनवादी गणतंत्र के संविधान और तीन अनुसरण बिंदुओं का उल्लंघन करता है। जबकि तिब्बती पक्ष का यह कहना है कि ज्ञापन में उल्लेखित तिब्बती जनता की जरूरतें संविधान एवं उसके स्वायत्तता के सिद्धांत के ढांचे एवं भावना के अंदर ही पूरी की जा सकती हैं और इन प्रस्तावों से तीन अनुसरण बिंदुओं का उल्लंघन या टकराव नहीं होता। हमारा यह मानना है कि यह मौजूदा टिप्पणी इन बातों का स्पष्टीकरण कर सकेगी।

तिब्बत की भविष्य की दशा के लिए आज़ादी चाहने की जगह एक स्वायत्तशासी व्यवस्था के द्वारा हल के लिए रास्ता निकालने हेतु परम पावन दलाई लामा ने 1974 में ही आंतरिक रूप से चर्चा शुरू कर दी थी। साल 1979 में चीनी नेता दैंग जियोपिंग ने तिब्बत की आज़ादी के अलावा अन्य सभी मसलों पर बातचीत एवं उसे हल करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद से परम पावन दलाई लामा ने तिब्बत के मसले के हल के लिए एक परस्पर स्वीकार्य बातचीत से हल निकालने के लिए कई प्रयास किए। ऐसा करके परम पावन दलाई लामा ने मध्यम मार्ग नीति का अटल रूप से पालन किया जिसका मतलब यह था कि मेलमिलाप और समझौते की भावना के द्वारा एक परस्पर स्वीकार्य और परस्पर लाभ वाला हल निकाला जा सके। इस भावना में पांच सूत्रीय शांति योजना और स्ट्रॉसबर्ग प्रस्ताव भी शामिल थे। लेकिन इन प्रयासों पर चीन की केंद्रीय सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने की वजह से और मार्च 1989 में तिब्बत में सैनिक शासन थोप देने एवं वहां के हालात ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से परम पावन ने यह अनुभव किया कि साल 1991 में यह मानने को विवश हुए कि स्ट्रॉसर्ब प्रस्ताव अप्रभावी हो गए हैं। इसके बावजूद परम पावन दलाई लामा ने मध्यम मार्ग नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ी।

चीन की केंद्रीय सरकार और परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों के बीच साल 2002 में फिर शुरु हुई वार्ता प्रक्रिया ने दोनों पक्षों को यह अवसर प्रदान किया कि वे अपना पक्ष साफ कर सकें और अपनी चिंताओं, जरूरतों और हितों को एक–दूसरे को अच्छी तरह समझा सकें। इसके अलावा चीन की केंद्रीय सरकार की असल चिंताओं, जरूरतों और हितों पर विचार करते हुए परम पावन दलाई लामा ने स्थिति की सचाई पर काफी गंभीरता से विचार किया। इससे पता चलता है कि परम पावन तिब्बत मसले के एक परस्पर फायदेमंद हल के लिए कितने लचीले, खुले, व्यावहारिक और सबसे बढ़कर कितने गंभीर हैं।

जुलाई, 2008 में हुए सातवें दौर की वार्ता में चीन की केंद्र सरकार से मिले सुझावों के जवाब में तिब्बती जनता के लिए वास्तविक स्वायत्तता का ज्ञापन तैयार किया गया था।

हालांकि, चीन की केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और ज्ञापन की मुख्य आलोचना उस प्रस्ताव के आधार पर नहीं लगती जो उसे आधिकारिक रूप से दिया गया था, बल्कि यह उस पुराने प्रस्ताव के आधार पर लगती है जिसे सार्वजनिक किया गया था और उन बयानों के आधार पर भी लगती है जिसे विभिन्न समय और संदर्भ में जारी किया गया था।

ज्ञापन और मौजूदा नोट इस बात पर मजबूती से जोर देता है कि परम पावन दलाई लामा आज़ादी या अलगाव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह चीन के संविधान के ढांचे के भीतर और उसके स्वायत्तता के सिद्धांत के तहत ही एक हल निकालने की बात कर रहे हैं जैसा कि वह पहले भी कई बार दोहरा चुके हैं।

साल 2008 में धर्मशाला में आयोजित तिब्बती समुदाय की खास आम सभा में इस बात की फिर से पुष्टि की गई थी कि फिलहाल लक्ष्य यह है कि मध्यम मार्ग नीति के आधार पर चीन सरकार के साथ वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी दोनों पक्षों से यह आग्रह किया है कि वार्ता प्रक्रिया शुरू की जाए। कई देशों ने यह राय जाहिर की है कि वार्ता के लिए ज्ञापन अच्छा आधार बन सकता है।

1. चीन जनवादी गणराज्य की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय एकता का सम्मान

परम पावन दलाई लामा ने बार–बार यह

कहा है कि वह तिब्बत को चीन जनवादी गणराज्य से अलग नहीं करना चाहते और वह तिब्बत के लिए आज़ादी नहीं चाहते। वह चीन जनवादी गणराज्य के भीतर ही एक टिकाऊ हल चाहते हैं। ज्ञापन में इस बात को सुस्पष्ट रूप से रखा गया है।

इस ज्ञापन में वास्तविक स्वायत्तता लागू करने की मांग की गई है, न कि आज़ादी या अर्द्ध आज़ादी या किसी भी तरह के छद्म आज़ादी की बात।

ज्ञापन के सार तत्व से यह बात साफ हो जाती है, जिसमें यह व्याख्या की गई है कि वास्तविक स्वायत्तता का मतलब क्या है। ज्ञापन में प्रस्तावित स्वायत्तता का स्वरूप और कोटि चीन जनवादी गणतंत्र के संविधान में दिए गए स्वायत्तता के सिद्धांतों के अनुरूप ही है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई स्वायत्तशासी क्षेत्रों में जिस तरह का स्वशासन लागू है उसी तरह की बात ज्ञापन में भी कही गई है और इन क्षेत्रों से भी किसी भी तरह से उस देश की स्वायत्तता या एकता को कोई चुनौती नहीं मिलती है जिसके वे अंग हैं। ये केंद्रीय सरकार के भीतर और संघीय विशेषताओं वाले एक सच्चे स्वायत्तशासी क्षेत्र हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई निष्पक्ष राजनेताओं सहित कई प्रेक्षकों और तमाम विद्वानों ने भी यह स्वीकार किया है कि यह ज्ञापन चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर ही स्वायत्तता की मांग है और इसमें कहीं से भी चीन से अलगाव या आज़ादी की बात नहीं की गई है। तिब्बत के इतिहास को लेकर चीन सरकार का दृष्टिकोण तिब्बती नागरिकों और दलाई लामा से अलग है और दलाई लामा इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि तिब्बती कभी भी चीन सरकार के दृष्टिकोण को नहीं मानेंगे। इतिहास एक पुरानी घटना है जिसे बदला नहीं जा सकता। हालांकि, परम पावन दलाई लामा का नजरिया आगे की ओर देखने वाला है,न कि पीछे की ओर देखने की। वह यह नहीं समझते कि इतिहास को लेकर दृष्टिकोण का यह अंतर चीन के भीतर ही तिब्बत के भविष्य के लिए परस्पर फायदेमंद हल निकालने में अड़चन हो सकता है।

ज्ञापन पर चीन की केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया से यह बात जाहिर होती है कि चीन सरकार अभी भी यह मानने पर अड़ी हुई है कि यह आज़ादी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए परम पावन का रणनीतिक प्रयास है।

परम पावन दलाई लामा तिब्बत की मौजूदा स्थिति की वैधानिकता को लेकर चीन जनवादी गणराज्य की चिंताओं और संवेदनशीलता से परिचित हैं। इस वजह से परम पावन दलाई लामा ने अपने दूतों के माध्यम से यह संदेश दिया है और सार्वजनिक रूप से भी यह कहा है कि वह स्वायत्तता के समझौते पर जनता का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं।

2. चीन जनवादी गणराज्य के संविधान का सम्मान

ज्ञापन में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि तिब्बती लोगों के लिए परम पावन दलाई लामा द्वारा मांगी जा रही वास्तविक स्वायत्तता चीन के संवैधानिक ढांचे के भीतर और उसमें वर्णित स्वायत्तता के सिद्धांत के भीतर ही दी जा सकती है, न कि उसके बाहर। राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता की अवधारणा में यह बुनियादी सिद्धांत निहित है कि अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय पहचान, भाषा, रीति–रिवाज, परंपराओं और संस्कृति का समानता एवं सहयोग पर आधारित एक बहुराष्ट्रीय राज्य में संरक्षण एवं बचाव हो सके।

संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि स्वशासन के अंगों की स्थापना की जाए जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एक संकेंद्रित समुदाय के रूप में ऐसी व्यवस्था के साथ रह सकें ताकि वे स्वायत्तता की ताकत का उपभोग कर सकें।

इस सिद्धांत के अनुरूप ही जारी तिब्बत में क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता पर श्वेत पत्र मई 2004 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं "खुद के भाग्य की नियंता और अपने मामलों की मालिक हैं।"

इसमें निहित सिद्धांतों के पैरामीटर के भीतर ही एक संविधान को समय की जरूरतों का समाधान करना चाहिए और उसे नई बदली हुई परिस्थितियों को भी स्वीकार करना चाहिए। चीन जनवादी गणतंत्र के नेताओं ने संविधान की व्याख्या और उसे लागू करने के मामले में इसके लचीलेपन का प्रदर्शन किया है और बदली हुई परिस्थितियों से मुकाबले के लिए इसमें संशोधन एवं बदलाव भी किए गए हैं।

यदि तिब्बती परिस्थिति में इसे लागू किया जाता है तो इस प्रकार के लचीलेपन से जैसा कि ज्ञापन में कहा गया है, निश्चित रूप से तिब्बती जरूरतों को संविधान के ढांचे के भीतर और उसके स्वायत्तता के सिद्धांत के भीतर ही पूरा किया जा सकता है।

3. तीन अनुसरण बिंदुओं का सम्मान

परम पावन दलाई लामा का पक्ष जैसा कि ज्ञापन में पेश किया गया है, किसी भी तरह से चीन जनवादी गणतंत्र की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को चुनौती नहीं देता या उसे सवालों के घेरे में नहीं खड़ा करता। लेकिन साथ ही, यह उम्मीद करना वाजिब है कि

ज्ञापन और मौजूदा नोट इस बात पर मजबूती से जोर देता है कि परम पावन दलाई लामा आज़ादी या अलगाव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह चीन के संविधान के ढांचे के भीतर और उसके स्वायत्तता के सिद्धांत के तहत ही एक हल निकालने की बात कर रहे हैं जैसा कि वह पहले भी कई बार दोहरा चुके हैं।

समाज में एकता, स्थिरता और सामजंस्य को बढ़ावा देने के लिए पार्टी को यह चाहिए कि वह तिब्बती संस्कृति, धर्म और पहचान पर खतरा बनने वाले अपने रवैए में बदलाव लाए।

ज्ञापन में चीन जनवादी गणतंत्र के समाजवादी व्यवस्था को भी कोई चुनौती नहीं दी गई है। न तो इसमें यह सुझाव दिया गया है कि इस व्यवस्था को बदला जाए या इसे तिब्बती क्षेत्र से बाहर किया जाए। समाजवाद पर परम पावन दलाई लामा के विचारों में कहा गया है, कि वह हमेशा समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो समाज के गरीब तबकों के बीच समानता को बढ़ावा देने और उन्हें उपर उठाने की बात करती है। चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर वास्तविक स्वायत्तता के आह्वान के लिए परम पावन दलाई लामा की मांग चीन के संविधान में निहित अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के लिए स्वायत्तता के सिद्धांतों को मान्यता देती है और इन सिद्धांतों के घोषित उद्देश्य के अनुरूप है।

जैसा कि ज्ञापन में अंकित किया गया है, स्वायत्तता के प्रावधानों को मौजूदा समय में जिस तरह से लागू किया गया है, उसमें तिब्बतियों को वास्तविक स्वायत्तता से पूरी तरह से वंचित किया गया है और उसमें तिब्बतियों को स्वयं पर शासन करने और अपने मामलों के मालिक बनने के अधिकार को देने में विफल रहा है।

आज, तिब्बतियों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय तिब्बतियों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। ज्ञापन में व्याख्यायित वास्तविक स्वायत्तता से तिब्बती इस बात में सक्षम हो सकेंगे कि वास्तविक स्वायत्तता के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें और इस प्रकार वे स्वायत्तता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप अपने मामलों के मालिक हो सकें। इस प्रकार वास्तविक स्वायत्तता के ज्ञापन में कहीं से भी तीन अनुसरण बिंदुओं का विरोध नहीं है।

जैसा कि ज्ञापन में अंकित किया गया है, स्वायत्तता के प्रावधानों को मौजूदा समय में जिस तरह से लागू किया गया है, उसमें तिब्बतियों को वास्तविक स्वायत्तता से पूरी तरह से वंचित किया गया है और उसमें तिब्बतियों को स्वयं पर शासन करने और अपने मामलों के मालिक बनने के अधिकार को देने में विफल रहा है।

4. चीन की केंद्रीय सरकार के पदानुक्रम और सत्ता का सम्मान

ज्ञापन में निहित प्रस्तावों में किसी भी तरह से चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस (एनपीसी) और चीन की केंद्रीय सरकार के अन्य अंगों की सत्ता को नकारने का भाव नहीं है। ज्ञापन में उल्लेखित प्रस्ताव केंद्र सरकार और उसके अंगों जैसे एनपीसी और तिब्बत की स्वायत्तशासी सरकार के पदानुक्रम का पूरी तरह से सम्मान करते हैं।

वास्तविक स्वायत्तता के किसी भी रूप का मतलब यह होता है कि उसमें केंद्र और स्वायत्तशासी स्थानीय सरकार के बीच सत्ता और जिम्मेदारियों का विभाजन और आवंटन हो, जैसे कानून बनाने एवं उसके रेगुलेशन की। निश्चित रूप से कानून को स्वीकार करने और उसके रेगुलेशन की ताकत स्वायत्तशासी क्षेत्र की योग्यता पर ही निर्भर करती है। यह ऐकिक राज्यों और संघीय ढांचे दोनों के लिए सच है।

संविधान में भी इस भावना को मान्यता दी गई है। स्वायत्तता पर संवैधानिक प्रावधानों की भावना साधारण प्रांतों को मिले अधिकारों से ज्यादा और उपर स्वायत्तशासी क्षेत्रों को व्यापक निर्णय करने का अधिकार देने की है। लेकिन आज स्वायत्तशासी क्षेत्रों के सभी नियमों एवं रेगुलेशन (संविधान की धारा 116) के लिए एनपीसी की स्थायी समिति से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि जिससे स्वायत्तशासी क्षेत्रों के पास ऐसे निर्णय करने का अधिकार बहुत कम रह जाता है जो चीन के अन्य प्रांतों से अलग स्थानीय दशाओं के अनूकूल हो।

जब भी सरकार के विभिन्न स्तरों (केंद्र सरकार एवं स्वायत्तशासी सरकार) के बीच निर्णय लेने की शक्तियों के बंटवारे एवं आवंटन की बात होती है, यह महत्वपूर्ण है कि परामर्श एवं सहयोग की प्रक्रिया को लागू किया जाए। इससे परस्पर समझ बढ़ती है और यह सुनिश्चित होता है कि नीतियों, कानून एवं रेगुलेशन में विरोधाभास और संभावित असंगतता कम से कम हो। इससे सरकार के विभिन्न अंगों को दी गई शक्तियों के इस्तेमाल में किसी तरह के विवाद उठने की संभावना भी कम होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया और तंत्र से ऐसा नहीं होता कि केंद्र और स्वायत्तशासी सरकार एक समान हो जाते हैं और ही न इनसे केंद्र सरकार के नेतृत्व को खारिज किया जा सकता है। संविधान या किसी अन्य तरीके से हासिल स्वायत्तता की व्यवस्था का यह मतलब नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकार समान हो गई है और न ही इससे केंद्र सरकार की शक्तियां सीमित या कमजोर होती हैं। इस उपाय का इरादा स्वायत्तशासी और केंद्रीय, दोनों सत्ताओं को कानूनी सुरक्षा मुहैया कराना है ताकि कोई भी एकतरफा तरीके से उस स्वायत्तता की बुनियादी विशेषताओं को न बदल सके जिसकी स्थापना की गई थी, और बुनियादी बदलावों के लिए कम से कम वार्ता प्रक्रिया शुरू हो।

5. विशिष्ट क्षमताओं आवंटन में जनसुरक्षा के पहलू को शामिल करने पर चिंता

ए– जनसुरक्षा

स्वायत्तशासी क्षेत्रों को आवंटित क्षमताओं में जन सुरक्षा के पहलू को शामिल करने पर ज्ञापन में चिंता जताई गई

है क्योंकि सरकार ने इसकी प्रत्यक्ष व्याख्या ऐसी की है कि यह प्रतिरक्षा का मामला है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षा दो अलग–अलग मामले हैं।

परम पावन दलाई लामा इस बात को लेकर साफ हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी चीन जनवादी गणराज्य की है और यह अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहना चाहिए। यह ऐसी क्षमता नहीं है जिसका इस्तेमाल स्वायत्तशासी क्षेत्र करें। ज्यादातर स्वायत्तशासी व्यवस्था में ऐसा ही होता है। वास्तव में ज्ञापन में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा का विशिष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है और यह महत्वपूर्ण बात कही गई है कि बहुसंख्यक सुरक्षा कर्मी तिब्बती समुदाय से ही होने चाहिए क्योंकि वे स्थानीय रीति–रिवाजों और परंपराओं को बखूबी समझते हैं। इसका फायदा यह होगा कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं के बीच कभी असामंजस्य की घटना दिखती है तो उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इस संदर्भ में ज्ञापन संविधान की धारा 120 के निहित सिद्धांतों (एलआरएनए की धारा 24 में भी प्रदर्शित) के अनुरूप ही है जिसमें कहा गया है,

"राष्ट्रीय स्वायत्तशासी क्षेत्र में स्वशासी सरकार के अंग देश की सैन्य व्यवस्था, स्थानीय व्यावहारिक जरूरतों के अनुरूप और स्टेट कौंसिल की मंजूरी से कानून–व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय जन सुरक्षा बलों का गठन कर सकते हैं।"

इस संदर्भ में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ज्ञापन में कभी भी तिब्बती क्षेत्रों से जन मुक्ति सेना (पीएलए) को हटाने की बात नहीं की गई है।

बी– भाषा

तिब्बतियों के लिए वास्तविक स्वायत्तता को लागू करने में तिब्बती भाषा के संरक्षण, इस्तेमाल और विकास की बात कई महत्वपूर्ण मसलों में से एक है। तिब्बत को तिब्बती क्षेत्रों में मुख्य या प्रधान भाषा के रूप में सम्मान देने की जरूरत पर जोर देने में कोई विवाद नहीं है क्योंकि चीन की केंद्र सरकार द्वारा *तिब्बत में क्षेत्रीय नस्लीय स्वायत्तता* पर जारी श्वेतपत्र में ऐसी ही बात कही गई है। यही नहीं, तिब्बत की क्षेत्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किए गए रेगुलेशन में भी कहा गया है, "तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में तिब्बती लोगों और हान चीनी भाषा पर बराबर ध्यान दिया जाएगा और तिब्बती भाषा प्रमुख होगी। " इसके अलावा ज्ञापन में इस्तेमाल किए गए "मुख्य भाषा" शब्द से यह साफ पता चलता है कि वहां अन्य भाषाओं का भी इस्तेमाल होता है।

अगर ज्ञापन में यह मांग नहीं है कि चीनी भाषा का भी इस्तेमाल और पढ़ाई होनी चाहिए तो इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि चीन जनवादी गणराज्य की इस मुख्य और आम भाषा को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। इस संदर्भ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि निर्वासन में रहने वाले तिब्बती नेतृत्व ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे निर्वासित तिब्बती लोग चीनी भाषा सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। इसलिए तिब्बतियों के अपनी भाषा पर जोर देने के तिब्बती प्रस्ताव की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि यह कोई अलगाववादी दृष्टिकोण है।

सी– जनसंख्या आव्रजन पर नियंत्रण

ज्ञापन में यह प्रस्ताव दिया गया है कि स्वायत्तशासी क्षेत्र की स्थानीय सरकार को इतनी ताकत मिलनी चाहिए कि वह किसी और क्षेत्र से तिब्बती क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों के आवास, बसाव, रोजगार या आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। यह स्वायत्त क्षेत्रों की एक आम विशेषता है और निश्चित रूप से चीन जनवादी गणराज्य के भीतर भी ऐसी मिसाले हैं।

कई देशों ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों या देशज और अल्पसंख्यक लोगों को देश के अन्य हिस्सों से होने वाले भारी आव्रजन से बचाने के लिए व्यवस्था बनाई है या कानून अपनाए हैं। ज्ञापन में इस बात को साफ तौर से कहा गया है कि यह सुझाव कतई नहीं है कि तिब्बती क्षेत्रों में वर्षों से रहने वाले गैर तिब्बती लोगों को बाहर किया जाए। परम पावन दलाई लामा और कशग ने भी अपने पहले के बयानों और परम पावन के दूतों ने चीनी पक्षकारों से वार्ता के दौरान भी इस बात को साफ किया है। 4 दिसंबर, 2008 को यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए परम पावन दलाई लामा ने यह बात दोहराई थी कि, " हमारा इरादा गैर तिब्बतियों को बाहर निकालने का नहीं है। हमारी चिंता मुख्यतः हान नस्ल और कई अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों को कई तिब्बती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वहां बसाने को लेकर है जिससे वहां की मूल निवासी तिब्बती जनसंख्या हाशिए पर जा रही है और इससे तिब्बत के नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है।" इससे यह बात साफ हो गई है कि परम पावन का यह सुझाव बिल्कुल नहीं है कि तिब्बत में सिर्फ तिब्बती लोग ही निवास करें, अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों के रहते हुए यह संभव नहीं है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि स्वायत्तशासी सरकार को इस बात की पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई हैं जिससे वे अस्थायी, मौसमी श्रमिकों और नए बसने वालों पर नियंत्रण रख सकें ताकि तिब्बती क्षेत्रों की नाजुक देशज जनसंख्या का बचाव हो सके।

ज्ञापन की प्रतिक्रिया में चीन सरकार इस प्रस्ताव को आंशिक रूप से खारिज कर चुकी है कि स्वायत्तशासी

ज्ञापन में इस बात को साफ तौर से कहा गया है कि यह सुझाव कतई नहीं है कि तिब्बती क्षेत्रों में वर्षों से रहने वाले गैर तिब्बती लोगों को बाहर किया जाए। परम पावन दलाई लामा और कशग ने भी अपने पहले के बयानों और परम पावन के दूतों ने चीनी पक्षकारों से वार्ता के दौरान भी इस बात को साफ किया है।

प्रशासन को चीन के अन्य हिस्सों से लोगों के आने और उनकी आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने का अधिकार मिले। यह प्रस्ताव इस आधार पर खारिज किया गया है कि, "संविधान और क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता पर कानून में इस बात के कोई प्रावधान नहीं हैं कि अस्थायी जनसंख्या के आवाजाही पर नियंत्रण लगाया जा सके।" लेकिन वास्तव में क्षेत्रीय राष्ट्रीयत स्वायत्तता के कानून की धारा 43 में इस तरह के रेगुलेशन का साफ तौर पर उल्लेख किया गया है: "कानूनी सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय स्वायत्तशासी क्षेत्र के स्वशासन के अंग अस्थायी जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं।" इस प्रकार ज्ञापन में इस तरह के जो प्रस्ताव दिए गए हैं वे कहीं से भी संविधान के खिलाफ नहीं हैं।

डी – धर्म

ज्ञापन में उठाया गया यह मसला कि तिब्बतियों को अपनी मान्यता के हिसाब से अपने धर्म के पालन की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, पूरी तरह से चीन जनवादी गणराज्य के संविधान में निहित धार्मिक आज़ादी के सिद्धांतों के अनुरूप ही है। यह कई देशा में स्वीकार किए गए इस सिद्धांत के अनुरूप भी है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए।

संविधान की धारा 36 में इस बात की गारंटी दी गई है कि कोई भी "किसी नागरिक को किसी धर्म को मानने या न मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।" हम भी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज यह देख रहे हैं कि सरकारी अधिकारी तिब्बतियों को अपने धर्म के पालन करने में कई तरह से दखल दे रहे हैं।

धर्म के पालन में गुरु और शिष्य के बीच आध्यात्मिक संबंध होता है और धार्मिक शिक्षण देने की जरूरत पड़ती है और यह सब धर्म के महत्वपूर्ण घटक हैं। इन पर प्रतिबंध लगाना धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन है। इसी प्रकार चीन सरकार द्वारा 18 जुलाई, 2007 को स्वीकार किए गए लामाओं के अवतार के प्रबंधन पर बने रेगुलेशन के अनुसार लामाओं के अवतार की पहचान में सरकार और उसकी संस्थाओं की सीधी भागीदारी एवं दखल भी संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भारी उल्लंघन है। तिब्बती लोगों में धर्म का पालन बहुत व्यापक और बुनियादी रूप से देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म के पालन को एक खतरे के रूप में देखते की जगह संबंधित अधिकारियों को इसका सम्मान करना चाहिए। परंपरागत रूप से या ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म हमेशा से ही तिब्बतियों और चीनी लोगों के बीच एक प्रमुख जोड़ने वाला और सकारात्मक कारक रहा है।

ई– एकल प्रशासन

एक स्वायत्तशासी क्षेत्र के भीतर प्रशासित होने की तिब्बतियों की इच्छा पूरी तरह से संविधान में दिए गए स्वायत्तता के सिद्धांत के अनुरूप है। तिब्बती राष्ट्रीयता की एकता की जरूरत का सम्मान करने का मूलाधार साफ तौर पर ज्ञापन में दिया गया है और "वृहत्तर या लघु तिब्बत" का कोई मतलब नहीं है। वास्तव में जैसा कि ज्ञापन में कहा गया है, यदि समुचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता कानून से ही प्रशासनिक सीमाओं में इस तरह के बदलाव की इजाजत मिल जाती है। इस प्रकार यह प्रस्ताव किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं करता। जैसा कि दलाई लामा के दूतों ने पिछले दौर की वार्ताओं में कई चीनी नेताओं जैसे, प्रधानमंत्री चाउ एनलाई, उप प्रधानमंत्री चेन ई और कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव हु योबांग के सामने यह बात उठाई थी कि हम सभी तिब्बती क्षेत्रों को एक प्रशासन के भीतर लाने के विचार का समर्थन करते हैं।

चीन जनवादी गणराज्य के कई वरिष्ठ तिब्बती नेता जैसे 10वें पंचेन लामा, नाग्पो नागवांग जिग्मे और बापा फुंत्सोक वांगयाल ने भी इसकी मांग की है और यह बात दुहराई है कि ऐसा करना चीन के संविधान और उसके कानूनों के अनुरूप ही होगा। साल 1956 में चीन की केंद्र सरकार ने वरिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य सांगयी येशी (टियान बाओ) सहित एक खास समिति बनाई जिसे सभी तिब्बती क्षेत्रों को एक स्वायत्तशासी क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए विस्तृत योजना तैयार करनी थी, लेकिन बाद में चरमपंथी वामपंथी तत्वों की वजह से इस कार्य को रोक देना पड़ा। तिब्बती क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई के तहत लाने के जरूरत की बुनियादी वजह यह है कि तिब्बती लोगों में स्वायत्तता को लेकर गहरी आकांक्षा है और वे एक जनता और अपनी संस्कृति एवं धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए इसे जरूरी समझते हैं। क्षेत्रीय धार्मिक स्वायत्तता पर संवैधानिक सिद्धांतों का बुनियादी आधार वाक्य और उद्देश्य भी है जैसा कि संविधान की धारा 4 में प्रतिबिंबित होता है।

तिब्बती लोगों की चिंता तिब्बती राष्ट्रीयता की एकता को लेकर है जिसका कि प्रस्ताव में सम्मान किया गया है और जो मौजूदा व्यवस्था के जारी रहते हुए संभव नहीं है। अपनी साझा ऐतिहासिक विरासत, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान, भाषा और तिब्बती पठार के विशिष्ट पर्यावरण के प्रति खास रिश्ते की वजह से सभी तिब्बती एक राष्ट्रीयता के रूप में जुड़ते हैं। चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर तिब्बतियों को एक राष्ट्रीयता के रूप में ही पहचाना जाता है, न कि कई राष्ट्रीयताओं के रूप में।

तिब्बती चाहे मौजूदा समय में तिब्बत स्वायत्तशासी प्रशासन के तहत रहते हों या दूसरे प्रांतों के तहत आने वाले काउंटी में, सभी एक तिब्बती राष्ट्रीयता से जुड़े हैं। परम पावन दलाई लामा सहित सभी तिब्बतियों की मुख्य चिंता तिब्बती संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों, राष्ट्रीय पहचान और पर्यावरण के संरक्षण एवं विकास की है। तिब्बती लोग यह मांग नहीं कर रहे हैं कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र का विस्तार किया जाए। वे केवल यह मांग कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रों को पहले से ही तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र माना जाता है उन्हें एकल प्रशासन के तहत लाया जाए जैसा कि चीन के अन्य स्वायत्तशासी क्षेत्रों में हुआ है। जब तक तिब्बतियों को खुद को एकल प्रशासन के तहत शासित होने का अवसर नहीं दिया जाता, तिब्बतियों की संस्कृति और उनके जीवन पद्धति का संरक्षण प्रभावी तरीके से नहीं हो सकता। आज आधे से ज्यादा तिब्बती जनसंख्या की प्राथमिकताओं और हितों का निर्धारण उन विभिन्न सरकारों द्वारा किया जाता है जिनमें खुद उनकी कोई प्रभावी भूमिका नहीं होती।

जैसा कि ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है, तिब्बती जनता केवल तभी वास्तविक क्षेत्रीय स्वायत्तता का लाभ उठा सकती है जब उसकी स्वयं की स्वायत्तशासी सरकार, जन कांग्रेस और स्वशासी सरकार के अन्य अंग हों जिनका अधिकार क्षेत्र समूचे तिब्बती राष्ट्रीयता पर हो। इस सिद्धांत का प्रतिबिंबन संविधान में भी है जिसमें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के क्षेत्रीय स्वायत्तता के पालन के अधिकार को मान्यता दी गई है (उन क्षेत्रों में जहां वे संक्रेदित समुदाय के रूप में रहते हैं) और इस अधिकार को भी कि वे "स्वायत्तता के ताकत के इस्तेमाल के लिए स्वशासन के अंगों का गठन कर सकते हैं।" (धारा 4) यदि क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता पर कानून के प्रस्तावना में विधिवत रूप से घोषित "अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के अपने आंतरिक मामलों के प्रशासन के सरकार द्वारा सम्मान और गारंटी" को इस तरह से व्याख्यायित किया गया कि इसमें ऐसे स्वायत्तशासी क्षेत्र बनाने का अधिकार शामिल नहीं है जिसमें एक समीपस्थ क्षेत्र में रहने वाले संक्रेदित समुदाय के सभी लोगों को रखा जाए तो इससे स्वायत्तता पर संवैधानिक सिद्धांतों की जड़ें कमजोर करने जैसा ही होगा।

तिब्बतियों को विभाजित रखने और उन्हें विभिन्न कानूनों एवं नियमों के तहत रखना इन लोगों को स्वायत्तता से वंचित रखने जैसा ही है और इससे उनके लिए अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख पाना कठिन होगा। केंद्र सरकार के लिए यह कोई असंभव बात नहीं है कि चीन में जहां कहीं ऐसी जरूरत हो उसके लिए जरूरी प्रशासनिक बदलाव किए जाएं। इनर मंगोलिया, निंगसिया और गाउंगक्सी स्वायत्तशासी क्षेत्र में ऐसा किया जा चुका है।

एफ–राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था

परम पावन दलाई लामा ने लगातार और बार–बार यह कहा है कि उनके सहित किसी का भी यह इरादा नहीं है कि तिब्बत में 1959 से पहले लागू पुरानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। भविष्य के स्वायत्तशासी तिब्बत की मंशा यह होगी कि तिब्बत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात में और सुधार किए जाएं न कि उसे पीछे की ओर ढकेला जाए। यह काफी परेशान करने वाली और उलझन वाली बात है कि सभी साक्ष्यों के विपरीत होने के बावजूद चीन सरकार लगातार दलाई लामा और उनके प्रशासन पर यह आरोप लगाती रही है कि उनका इरादा पुरानी व्यवस्था को फिर से लाने का है।

चीन सहित दुनिया के सभी देशों और समाजों में पहले ऐसी राजनीतिक व्यवस्था रही है जिसे आज की दुनिया में किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राचीन तिब्बती व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। आज दुनिया सामाजिक और राजनीतिक रूप से विकसित हो गई है और मानवाधिकारों को मान्यता एवं जीवन स्तर के मामले में काफी प्रगति हो चुकी है। निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों ने भी अपनी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था और शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा कई अन्य संस्थाओं का विकास किया है।

इस तरह से आज निर्वासित तिब्बती दुनिया के अन्य देशों के नागरिकों की बराबरी करने लगे हैं। यह बात भी स्पष्ट है कि चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर चीनी शासन के तहत रहने वाले तिब्बती नागरिकों के भी सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि, यदि चीन जनवादी गणतंत्र के अन्य हिस्सों के नागरिकों से तुलना की जाए तो तिब्बती जनता सबसे पिछड़ी हुई है और वहां तिब्बतियों के मानवाधिकारों का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है।

6. मुख्य मसलों की पहचान

परम पावन दलाई लामा और निर्वासित नेतृत्व के अन्य सदस्यों की कुछ भी व्यक्तिगत मांग नहीं है। परम पावन दलाई लामा की चिंता सिर्फ तिब्बतियों के अधिकार और कल्याण को लेकर है। इसलिए जिस बुनियादी मसले का समाधान करने की जरूरत है वह यह है कि वास्तविक स्वायत्तता को ईमानदारी से लागू किया जाए

जिससे तिब्बती जनता अपनी प्रतिभा और जरूरतों के हिसाब से खुद पर शासन कर सके।

परम पावन दलाई लामा तिब्बती जनता की तरफ से बोलते हैं क्योंकि इस जनता के साथ उनका पूरे भरोसे पर आधारित गहरा एवं ऐतिहासिक रिश्ता है। वास्तव में परम पावन दलाई लामा के तिब्बत में लौटने को लेकर तिब्बतियों में जिस तरह से पूरी तरह से रजामंदी है वैसा अन्य किसी मसले को लेकर नहीं है।

इस बात में कोई भी विवाद नहीं हो सकता कि परम पावन दलाई लामा तिब्बती जनता के वैधानिक प्रतिनिधि हैं और उन्हें निश्चित रूप से तिब्बती जनता के सच्चे प्रतिनिधि और प्रवक्ता के रूप में देखा जाता है। वास्तव में परम पावन दलाई लामा से वार्ता करने के एकमात्र तरीके से ही तिब्बत के मसले को हल किया जा सकता है। इस सचाई को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है।

परम पावन दलाई लामा द्वारा अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि तिब्बत के आंदोलन के साथ उनके जुड़ने का उद्देश्य अपने लिए किसी निश्चित व्यक्तिगत अधिकार या राजनीतिक पद का दावा करना नहीं है, न ही वह निर्वासित तिब्बती प्रशासन में हिस्सेदारी मांगने का कोई प्रयास कर रहे हैं। एक बार चीन सरकार के साथ समझौता हो जाने पर निर्वासित तिब्बती सरकार भंग कर दी जाएगी और तिब्बत में काम कर रहे तिब्बतियों की ही तिब्बत में प्रशासन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी होगी। परम पावन दलाई लामा ने कई अवसरों पर यह बात साफ की है कि वह तिब्बत में कोई भी राजनीतिक पद नहीं लेंगे।

7. परम पावन दलाई लामा का सहयोग

परम पावन दलाई लामा ने पेशकश की है और वह इसके लिए तैयार भी हैं कि एक औचारिक बयान जारी कर अपनी स्थिति और ऊपर वर्णित मामलों पर अपने इरादों पर चीन सरकार के संदेहों और चिंताओं को दूर करें।

यह बयान परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों और चीन की केंद्रीय सरकार के बीच गहन विचार–विमर्श के बाद तैयार होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे चीन सरकार और तिब्बती जनता की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होगी। यह महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष किसी भी तरह की चिंता का समाधान सीधे एक–दूसरे से बात कर करें और इन मसलों को वार्ता प्रक्रिया के बीच रोड़ा न बनाएं जैसा कि पहले हो चुका है।

परम पावन दलाई लामा यह प्रयास यह मानते हुए कर रहे हैं कि चीन के संविधान में वर्णित स्वायत्ता के सिद्धांतों और तिब्बती जनता के हितों के अनुरूप चीन जनवादी गणतंत्र के साथ कुछ साझी जमीन तलाशना संभव है। इस भावना के साथ ही परम पावन दलाई लामा की यह अपेक्षा और उम्मीद है कि चीन के प्रतिनिधि ज्ञापन और इस नोट से मिले अवसरों का इस्तेमाल बातचीत को गहराई प्रदान करने और इसमें पर्याप्त प्रगति लाने में करेंगे ताकि पारस्परिक समझ का विकास हो सके।

रजिस्ट्रेशन आफ न्यूजपेपर्ज ;सेंट्रल रूल्स 1956 के आठवें नियम के अंतर्गत 'तिब्बत देश' के स्वामित्व व अन्य विषयों संबंधी वक्तव्य :–

1. प्रकाशन का स्थान : 10–एच लाजपत नगर–3, नई दिल्ली–110024
2. प्रकाशन की अवधि : मासिक
3. मुद्रक : जमयांग दोरजी
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : 10–एच लाजपत नगर–3, नई दिल्ली–110024
4. प्रकाशक का नाम : जमयांग दोरजी
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : 10–एच, लाजपत नगर–3, नई दिल्ली – 110024
5. संपादक का नाम : जमयांग दोरजी
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : 10–एच, लाजपत नगर–3, नई दिल्ली – 110024
6. मालिक का नाम : जमयांग दोरजी

मैं, जमयांग दोरजी, यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गयी सूचनाएं मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

जमयांग दोरजी
दिनांक 1 फरवरी, 2010
प्रकाशक के हस्ताक्षर